



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 750]

No. 750]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 21, 2003/श्रावण 30, 1925

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 21, 2003/SRAVANA 30, 1925

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 21 अगस्त, 2003

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अधिनिर्णायक) विनियम, 2003

का.आ. 953(अ).— बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की, धारा 11 की उप-धारा (1) के साथ पठित, धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा प्रतिभूतियों में विनिधानकर्ताओं की शिकायत-मुद्दों को दूर करने के लिए और उससे संबद्ध या उससे आनुषंगिक मामलों के लिए अधिनिर्णायक (ओबंड्समन) के कार्यालय की स्थापना का उपबंध करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

अध्याय I

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1. (1) इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अधिनिर्णायक) विनियम,

(1)

2003 कहा जा सकेगा ।

- (2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

परिभाषाएँ

2. (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "अधिनियम" से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) अभिप्रेत है ;

(ख) "पंचाट" से इन विनियमों के अनुसार दिए गए अधिनिर्णायक के निदेश या आदेश के रूप में निष्कर्ष अभिप्रेत है ;

(ग) "प्राधिकृत प्रतिनिधि" से शिकायतकर्ता या शिकायत के किसी अन्य पक्षकार द्वारा उसकी ओर से कृत्य करने और अधिनिर्णायक के समक्ष कार्यवाहियों में उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए सम्यक् रूप से नियुक्त और प्राधिकृत व्यक्ति अभिप्रेत है ;

- (घ) "बोर्ड" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अभिप्रेत है ;
- (ङ) "अध्यक्ष" से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;
- (च) "शिकायत" से लिखित अभ्यावेदन जिसमें इन विनियमों के विनियम 13 में यथा विनिर्दिष्ट शिकायत-मुद्दा अंतर्विष्ट है अभिप्रेत है ;
- (छ) "शिकायतकर्ता" से कोई विनिधानकर्ता जो अधिनिर्णायक के पास शिकायत दाखिल करता है और जिसमें बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त विनिधानकर्ता (निवेशक) संघ सम्मिलित है अभिप्रेत है ;
- (ज) "मध्यवर्ती" से अधिनियम की धारा 12 में निर्दिष्ट व्यक्ति अभिप्रेत है और सम्मिलित है ;
- (झ) "विनिधानकर्ता" से व्यक्ति जो प्रतिभूतियों में विनिधान या क्रय या विक्रय या व्यौहार करता है अभिप्रेत है ;

- (ग) "सूचीबद्ध कंपनी" से कंपनी जिसकी प्रतिभूतियाँ मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं और जिसमें पब्लिक कंपनी जो मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में इसकी प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध कराने का इरादा रखती है सम्मिलित है ;
- (ट) "सदस्य" से बोर्ड का सदस्य अभिप्रेत है और जिसमें अध्यक्ष सम्मिलित है ;
- (उ) "अधिनिर्णायक" से इन विनियमों के विनियम 3 के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इसमें वैतनिक अधिनिर्णायक सम्मिलित है ;
- (ड) "प्रतिभूतियाँ" से प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 2 के खंड (ज) में यथा परिभाषित प्रतिभूतियाँ अभिप्रेत हैं ;
- (ढ) "वैतनिक अधिनिर्णायक" से विनिर्दिष्ट

क्षेत्रीय अधिकारिता में विनिर्दिष्ट मामले या मामलों की बाबत अधिनिर्णायक के रूप में कार्य करने के प्रयोजन के लिए विनियम 9 के अधीन नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है और जिसके लिए उसे ऐसे व्यय, मानदेय या आसीन-फीस अदा किये जा सकेंगे जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर अवधारित किये जायें ।

- (2) इन विनियमों में उपयोग किये गये और अपरिभाषित किंतु अधिनियम में अथवा अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों में परिभाषित शब्दों और पदों के अर्थ अधिनियम में अथवा अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों में क्रमशः जो उनके लिए नियत हैं होंगे ।

अध्याय II

अधिनिर्णायक के कार्यालय की स्थापना

स्थापना और नियुक्ति

3. (1) ऐसी तारीख से जो बोर्ड, आदेश द्वारा निश्चित कर सकेगा, इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए अधिनिर्णायक का कार्यालय स्थापित किया जायेगा ।
- (2) बोर्ड, चयन समिति की सिफारिश पर, ऐसी क्षेत्रीय अधिकारिता के लिए एक या अधिक अधिनिर्णायकों की नियुक्ति कर सकेगा जैसा आदेश द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाये ।
- (3) उप-विनियम (2) में निर्दिष्ट चयन समिति निम्नलिखित सदस्यों से गठित होगी, अर्थात्:-
- (i) उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले ;
- (ii) विशेषज्ञ वित्तीय बाजार प्रचालनों से संबंधित

क्षेत्र में अथवा विधि, वित्त या अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान तथा अनुभव रखने वाले, अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले ;

(iii) बोर्ड के प्रतिनिधि जो कार्यपालक निदेशक से नीचे की पंक्ति का न हो जो चयन समिति का सचिव होगा, अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले ।

(4) बोर्ड के अनुरोध पर, चयन समिति व्यक्तियों का पैनल भी तैयार कर सकेगी जिनमें से व्यक्ति को वैतनिक अधिनिर्णायक के रूप में नियुक्त किया जायेगा ।

(5) उप-विनियम (4) के अधीन पैनल दो वर्षों की अधिकतम कालावधि के लिए प्रवृत्त रहेगा और समय-समय पर पुनर्गठित किया जायेगा ।

परंतु यह कि विद्यमान पैनल में कोई व्यक्ति पुनर्गठित पैनल में सम्मिलित किये जाने के लिए पात्र होगा ।

कार्यालय का स्थान

4. (1) अधिनिर्णायक का कार्यालय बोर्ड के प्रधान

कार्यालय में स्थित होगा और यदि एक से अधिक अधिनिर्णायक नियुक्त किये जाते हैं तब किसी ऐसे अधिनिर्णायक का कार्यालय बोर्ड के किसी अन्य कार्यालय या किसी अन्य स्थान जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाये पर स्थित हो सकेगा ।

परंतु यह कि वैतनिक अधिनिर्णायक जब किसी विनिर्दिष्ट शिकायत या शिकायतों के लिए नियुक्त हो ऐसे स्थान पर स्थित होगा जो विनिर्दिष्ट किया जाये ।

(2) शिकायतों का शीघ्र निपटारा करने के लिए, अधिनिर्णायक या वैतनिक अधिनिर्णायक, यथास्थिति, उसकी अधिकारिता के क्षेत्र के भीतर ऐसे स्थानों पर बैठकें कर सकेगा जैसा उसके द्वारा आवश्यक और समुचित माना जाये ।

(3) बोर्ड परिसर और अन्य अवसंरचनाएँ जिनमें अधिनिर्णायक या वैतनिक अधिनिर्णायक, यथास्थिति, के कार्यालय के लिए स्टाफ या सचिवालयिक सहायता सम्मिलित है उपलब्ध

करा सकेगा ।

अर्हता

5.

अधिनिर्णायक के रूप में नियुक्त किये जाने
के लिए व्यक्ति -

(i) भारत का नागरिक होगा ;

(ii) उच्च नैतिक सत्यनिष्ठा वाला होगा ;

(iii) पैंतालीस वर्षों की आयु से कम की आयु का
नहीं होगा ; और

(iv) या तो

(क) सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश होगा या जिला
न्यायाधीश नियुक्त किये जाने के लिए अर्हित
होगा या

(ख) किसी विनियामक निकाय में सेवा का कम से
कम दस वर्षों का अनुभव रखने वाला होगा
या

(ग) दस वर्षों से अन्यून कालावधि के लिए विधि,

वित्त, निगम मामलों, अर्थशास्त्र, प्रबंध या प्रशासन में विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाला होगा ; या

- (घ) 10 वर्षों से अन्यून कालावधि के लिए विनिधानकर्ता संरक्षण से संबंधित मामलों को निपटाने का अनुभव रखने वाला बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त विनिधानकर्ता (निवेशक) संघ का पदाधिकारी होगा ।

निरर्हता

6. (1) व्यक्ति अधिनिर्णायक का पद धारण करने के लिए अर्हित नहीं होगा यदि -

- (i) वह अनुन्मोचित दिवालिया है ;
- (ii) उसे अपराध जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित हो का सिद्धदोष ठहराया गया है ;
- (iii) उसे विकृत चित्त का पाया गया है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसी घोषणा विद्यमान है ;
- (iv) उसे किसी अपराध जिसमें आर्थिक अपराध सम्मिलित हों के लिए आरोप पत्र दिया गया

हो ; या

- (V) वह मध्यवर्ती या सूचीबद्ध कंपनी के कार्यालय में पूर्णकालिक निदेशक रहा हो और कम से कम 3 वर्षों की कालावधि व्यपगत न हो गयी हो ।

पदावधि

7. (1) अधिनिर्णायक के रूप में नियुक्त व्यक्ति पाँच वर्षों से अनधिक अवधि के लिए पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा ।

परंतु यह कि कोई व्यक्ति सत्तर वर्षों की आयु पूरी कर लेने के पश्चात् अधिनिर्णायक का पद धारण नहीं करेगा ।

- (2) बोर्ड, किसी भी समय, उप-विनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट कालावधि के अवसान के पूर्व उसे लिखित रूप में तीन मास से अन्यून सूचना या उसके बदले में तीन मास के वेतन और भत्ते देते हुए अधिनिर्णायक की सेवाएँ समाप्त कर सकेगा, और अधिनिर्णायक को भी उसका पद त्यागने का अधिकार होगा, किसी भी समय, उप-विनियम (1) के अधीन

विनिर्दिष्ट कालावधि के अवसान के पूर्व,
बोर्ड को लिखित रूप में तीन मास से अन्यून
की सूचना देते हुए ।

पारिश्रमिक

8.

अधिनिर्णायक को संदेय वेतन, भत्ते, मानदेय
या फीस, और की सेवा के अन्य निबंधन
और शर्तें बोर्ड द्वारा समय-समय पर
अवधारित किये जायेंगे ।

वैतनिक अधिनिर्णायक

9. (1)

विनियम 3 के उप-विनियम (2) के अधीन
अधिनिर्णायक की नियुक्ति के होते हुए भी,
बोर्ड विनियम 3 के उप-विनियम (4) के
अधीन तैयार किए गए पैनल में से वैतनिक
अधिनिर्णायक के रूप में व्यक्ति को नियुक्त
कर सकेगा, विनिर्दिष्ट क्षेत्रीय अधिकारिता में
विनिर्दिष्ट मामले या मामलों की बाबत
अधिनिर्णायक के रूप में कार्य करने के
प्रयोजन के लिए, जैसा नियुक्ति के आदेश में
विनिर्दिष्ट किया जाये ।

(2)

व्यक्ति वैतनिक अधिनिर्णायक के रूप में
नियुक्त किये जाने के लिए पात्र होगा :-

- (i) जिसने कम से कम दस वर्षों के लिए केंद्रीय या राज्य सरकार के अधीन न्यायिक पद या कार्यपालक पद धारण किया हो या
 - (ii) जो उपभोक्ता या विनिधानकर्ता संरक्षण से संबंधित मामलों में कम से कम दस वर्षों का अनुभव रखता है या
 - (iii) जो कम से कम 10 वर्षों के लिए निगम मामलों में विधि व्यवसायी रहा हो या
 - (iv) जिसने कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 4क के अर्थ के भीतर किसी लोक वित्तीय संस्था या विनियामक निकाय में दस वर्षों की न्यूनतम कालावधि के लिए सेवा की हो ।
- (3) बोर्ड द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट के सिवाय, वैतनिक अधिनिर्णायक समस्त शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग करेगा जो इन विनियमों के अधीन अधिनिर्णायक में निहित हैं ।
- (4) वैतनिक अधिनिर्णायक को उसके द्वारा दी गई

सेवाओं के लिए ऐसी फीस या मानदेय और भत्ते अदा किये जायेंगे, जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाये ।

क्षेत्रीय अधिकारिता

10.

प्रत्येक अधिनिर्णायक या वैतनिक अधिनिर्णायक क्षेत्र के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करेगा जैसा बोर्ड द्वारा आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये ।

अध्याय III

अधिनिर्णायक की शक्तियाँ और कृत्य

साधारण

11.

अधिनिर्णायक के पास निम्नलिखित शक्तियाँ और कृत्य होंगे :-

- (क) किसी मध्यवर्ती या सूचीबद्ध कंपनी या दोनों के खिलाफ विनियम 13 में विनिर्दिष्ट शिकायतों को प्राप्त करना ;
- (ख) ऐसी शिकायतों पर विचार करना और सौहार्दपूर्ण समझौते द्वारा उसके निवारण को सुकर बनाना ;
- (ग) पक्षकारों के बीच विवाद के मैत्रीपूर्ण या सौहार्दपूर्ण समझौते को अनुमोदित करना ;
- (घ) मैत्रीपूर्ण या सौहार्दपूर्ण समझौते द्वारा उसका निपटारा करने की असफलता की दशा में ऐसी शिकायतों का न्यायनिर्णयन करना । -

अन्य शक्तियाँ और कृत्य

12. (1)

अधिनिर्णायक -

- (क) बोर्ड के परामर्श से उसके कार्यालय के लिए वार्षिक बजट तैयार करेगा और अनुमोदित बजट के उपबंधों के भीतर और के अनुसार व्यय उपगत करेगा ;
- (ख) प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन मास के भीतर बोर्ड को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें उसके कार्यालय के क्रियाकलापों का साधारण पुनर्विलोकन अंतर्विष्ट हो ; और
- (ग) समय-समय पर बोर्ड को ऐसी जानकारी देगा जो बोर्ड द्वारा अपेक्षित की जाये ।
- (2) अधिनिर्णायक का प्रत्येक वित्तीय वर्ष प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होगा और वार्षिक रिपोर्ट ऐसे प्ररूप और रीति में दी जायेगी जैसा बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये ।

अध्याय IV

शिकायत-मुद्दे को दूर करने के लिए प्रक्रिया

शिकायत के आधार

13.

व्यक्ति निम्नलिखित आधारों में से किसी एक या अधिक पर शिकायत या तो बोर्ड को या संबद्ध अधिनिर्णायक को दाखिल कर सकेगा:-

- (i) कंपनियों की प्रतिभूतियों अथवा पारस्परिक निधियों या सामूहिक विनिधान स्कीमों की यूनिटों के सार्वजनिक निर्गम की बाबत प्रतिदाय आदेशों, आबंटन पत्रों की अप्राप्ति ;
- (ii) शेयर प्रमाणपत्रों, यूनिट प्रमाणपत्रों, डिबेंचर प्रमाणपत्रों, बोनस शेयरों की अप्राप्ति ;
- (iii) शेयरधारकों या यूनिट-धारकों द्वारा लाभांश की अप्राप्ति ;
- (iv) डिबेंचरों पर ब्याज, डिबेंचरों की मोचन रकमों या डिबेंचरों पर ब्याज के विलंबित भुगतान पर ब्याज की अप्राप्ति ;

(v) आवेदन धनराशियों के विलंबित प्रतिदाय पर ब्याज की अप्राप्ति ;

(vi) संविभागों से संबंधित वार्षिक रिपोर्टों या विवरणों की अप्राप्ति ;

(vii) पारस्परिक निधि से मोचन रकम या सामूहिक विनिधान स्कीमों से प्रत्यागमों की अप्राप्ति ;

(viii) निर्गमकर्ता कंपनी, पारस्परिक निधि, सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी या निक्षेपागार द्वारा नियत समय के भीतर प्रतिभूतियों का अनंतरण ;

(ix) अधिग्रहण, क्रय द्वारा वापस लेने के प्रस्ताव या असूचीबद्धता में प्रस्ताव पत्र या प्रतिफल की अप्राप्ति ;

(X) निगमित फायदों को धारण करने या निगमित फायदों की बाबत किन्हीं शिकायत-मुद्दों के विवरण की अप्राप्ति, आदि ;

(xi) सूचीबद्ध कंपनी के सार्वजनिक, साधिकार या जोनस निर्गम की बाबत कोई शिकायत-मुद्दा ;

(xii) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 55क के अधीन समाविष्ट मामलों में से कोई ;

(xiii) मध्यवर्ती या सूचीबद्ध कंपनी के खिलाफ प्रतिभूतियों में निर्गम या व्यापार की बाबत कोई शिकायत-मुद्दा ।

शिकायत दाखिल करने की प्रक्रिया

14. (1)

कोई व्यक्ति जिसके पास विनियम 13 में विनिर्दिष्ट मामलों में से किसी से संबंधित सूचीबद्ध कंपनी या मध्यवर्ती के खिलाफ शिकायत-मुद्दा हो स्वयं अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि या बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त किसी निवेशकर्ता (निवेशक) संघ के माध्यम से, अधिनिर्णायक को सूचीबद्ध कंपनी या मध्यवर्ती के खिलाफ शिकायत कर सकेगा जिसकी अधिकारिता के भीतर ऐसी सूचीबद्ध कंपनी या मध्यवर्ती का रजिस्ट्रीकृत या निगमित कार्यालय स्थित है ।

परंतु यह कि यदि बोर्ड ने विशिष्ट परिक्षेत्र या क्षेत्रीय अधिकारिता के लिए किसी अधिनिर्णायक को अधिसूचित नहीं किया है, शिकायतकर्ता बोर्ड के प्रधान कार्यालय में स्थित अधिनिर्णायक से सक्षम अधिकारिता के अधिनिर्णायक को उसकी शिकायत अग्रेषित करने के लिए अनुरोध कर सकेगा।

- (2) शिकायत इन विनियमों की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप में शिकायतकर्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि (जो विधि व्यवसायी न हो) द्वारा लिखित रूप में सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और दस्तावेजों, यदि कोई हों, द्वारा समर्थित होगी।

कोई शिकायत अधिनिर्णायक को नहीं की जायेगी -

- (क) जब तक कि शिकायतकर्ता ने, बोर्ड या संबद्ध अधिनिर्णायक को शिकायत करने के पूर्व, शिकायत में नामित सूचीबद्ध कंपनी या मध्यवर्ती को लिखित अभ्यावेदन न किया हो और सूचीबद्ध कंपनी या मध्यवर्ती ने,

यथास्थिति, शिकायत को नामंजूर न कर दिया हो अथवा शिकायतकर्ता ने संबद्ध सूचीबद्ध कंपनी या मध्यवर्ती द्वारा उसका अभ्यावेदन प्राप्त किये जाने के पश्चात् एक मास की कालावधि के भीतर कोई उत्तर प्राप्त न किया हो अथवा शिकायतकर्ता का समाधान सूचीबद्ध कंपनी या मध्यवर्ती द्वारा उसको दिए गए उत्तर से न हुआ हो ;

(ख) जब तक कि शिकायत शिकायतकर्ता द्वारा उसकी शिकायत की नामंजूरी की संसूचना की प्राप्ति की तारीख से छह मास के भीतर अथवा उपर्युक्त खंड (क) के अधीन सूचीबद्ध कंपनी या मध्यवर्ती द्वारा शिकायत की प्राप्ति के पश्चात् सात मास के भीतर न की गयी हो ;

(ग) यदि शिकायत उसी विषय वस्तु की बाबत है जिसका निपटारा बोर्ड के कार्यालय या किन्हीं पूर्व कार्यवाहियों में संबद्ध अधिनिर्णायक के माध्यम से हो गया था, चाहे उसी शिकायतकर्ता से अथवा विषय वस्तु पर अन्य शिकायतकर्ताओं में से किसी एक या अधिक

अथवा संबद्ध पक्षकारों में से किसी एक या अधिक के साथ प्राप्त हुई हो या न हुई हो ;

- (घ) यदि शिकायत उसी विषय वस्तु से संबद्ध होती है जिसके लिए बोर्ड या किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या मध्यस्थ या किसी अन्य मंच के समक्ष कोई कार्यवाहियाँ लंबित हैं अथवा डिक्री या पंचाट या अंतिम आदेश किसी ऐसे सक्षम प्राधिकरण, न्यायालय, न्यायाधिकरण, मध्यस्थ या मंच द्वारा पहले ही से पारित कर दिया गया हो ;
- (ङ) यदि शिकायत विषय की बाबत या से संबद्ध है जिसके लिए कार्रवाई अधिनियम की धारा 11(4) या अधिनियम के अध्याय VI के अधीन या अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (3) के अधीन या अधिनियम के अधीन बनाये गये किन्हीं अन्य विनियमों के अधीन बोर्ड द्वारा कर ली गयी हो ।
- (4) अधिनिर्णायक आरंभ में ही उप-विनियम (3) के अधीन विनिर्दिष्ट आधारों में से किसी पर शिकायत को खारिज कर सकेगा या जब ऐसी

शिकायत उसकी राय में तुच्छ हो ।

जानकारी मंगाने की शक्ति 15. (1)

इन विनियमों के अधीन उसके कर्तव्यों का पालन करने के प्रयोजन के लिए, अधिनिर्णायक शिकायत में नामित सूचीबद्ध कंपनी या मध्यवर्ती अथवा किसी अन्य व्यक्ति, संस्था या प्राधिकरण से शिकायत की विषय वस्तु से संबंधित कोई जानकारी उपलब्ध कराने या किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रति देने की अपेक्षा कर सकेगा जो इसके या उसके कब्जे में है या होनी अभिकथित है ।

परंतु यह कि किसी पर्याप्त कारण के बिना उप-विनियम (1) के अधीन की गई अपेक्षा का अनुपालन करने में सूचीबद्ध कंपनी या मध्यवर्ती के असफल रहने की दशा में, अधिनिर्णायक, यदि वह ठीक समझे, अनुमान कर सकेगा कि जानकारी, यदि उपलब्ध करायी गयी हो या प्रतियाँ यदि दी गयी हों, सूचीबद्ध कंपनी या मध्यवर्ती के प्रति अननुकूल होगी ।

- (2) अधिनिर्णायक उसके कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान उसके ज्ञान या कब्जे में आने वाली किसी जानकारी या दस्तावेज की गोपनीयता बनाये रखेगा और किसी व्यक्ति को ऐसी जानकारी या दस्तावेज प्रकट नहीं करेगा विधि द्वारा अन्यथा अपेक्षित के सिवाय या ऐसी जानकारी या दस्तावेज देने वाले व्यक्ति की सम्मति से :

परंतु यह कि उप-विनियम (2) की कोई बात अधिनिर्णायक को अन्य पक्षकार या पक्षकारों को शिकायत में पक्षकार द्वारा दी गई जानकारी या दस्तावेज को प्रकट करने से नहीं रोकेगी, जहां तक उसके द्वारा कार्यवाहियों में नैसर्गिक न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांतों का अनुपालन करने के लिए युक्तियुक्त रूप से अपेक्षित समझे जायें ।

परंतु यह और कि उप-विनियम (2) के उपबंध बोर्ड को अधिनिर्णायक द्वारा किए गए प्रकटीकरणों या दी गई जानकारी अथवा किसी रोजनामचे या समाचारपत्र में

अधिनिर्णायक के पंचाट के प्रकाशन अथवा किसी न्यायालय, मंच या प्राधिकरण के समक्ष उसके दाखिल किये जाने के संबंध में लागू नहीं होंगे।

पारस्परिक करार द्वारा
समझौता

16. (1)

यथासाध्य शीघ्रता से ऐसा करने के लिए, अधिनिर्णायक किसी शिकायत की प्राप्ति की सूचना शिकायत में नामित सूचीबद्ध कंपनी के रजिस्ट्रीकृत या निगमित कार्यालय अथवा मध्यवर्ती के कार्यालय को भेजी गई शिकायत की प्रति के साथ कारित करेगा और शिकायतकर्ता और शिकायत में नामित सूचीबद्ध कंपनी या मध्यवर्ती के बीच करार या मध्यस्थता द्वारा शिकायत के समझौते को अग्रसर करने का प्रयास करेगा।

(2)

यदि कोई सौहार्दपूर्ण समझौता या मैत्रीपूर्ण करार पक्षकारों के बीच हो जाता है, तो अधिनिर्णायक ऐसे समझौते या करार के निबंधनों के अनुसार उसकी तारीख से एक मास के भीतर पंचाट पारित करेगा और पक्षकारों को पंचाट में अभिलिखित निबंधनों के अनुसार उनकी बाध्यताओं का पालन करने

का निदेश देगा ।

- (3) शिकायत के समझौते को अग्रसर करने के प्रयोजन के लिए, अधिनिर्णायक ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण कर सकेगा और ऐसी कार्यवाइयाँ कर सकेगा जैसा वह समुचित समझे ।

न्यायनिर्णयन पर पंचाट

17. (1) शिकायत की प्राप्ति के एक मास की कालावधि या ऐसी विस्तारित कालावधि जो अधिनिर्णायक द्वारा अनुज्ञात की जाये के भीतर पारस्परिक प्रतिग्राह्य करार द्वारा मामले का निवारण न होने की दशा में, वह, उसके समक्ष रखी गई सामग्री के आधार पर और पक्षकारों को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात्, लिखित रूप में उसका पंचाट देगा या कोई अन्य निदेश या आदेश पारित करेगा जो वह समुचित माने ।

- (2) न्यायनिर्णयन पर पंचाट अधिनिर्णायक द्वारा शिकायत के दाखिल किये जाने की तारीख से तीन मास की कालावधि के भीतर दिया जायेगा ।

परंतु यह कि कोई पंचाट केवल इस तथ्य के कारण से अविधिमान्य नहीं हो जायेगा कि पंचाट तीन मास की उक्त कालावधि के पश्चात् दिया गया था ।

- (3) अधिनिर्णायक न्यानिर्णयन के पक्षकारों को उसका पंचाट पंचाट के अधीन उनकी बाध्यताओं का पालन करने के लिए भेजेगा ।

पंचाट का सुधार

18. (1) पंचाट की प्राप्ति से पंद्रह दिनों के भीतर पक्षकार, अन्य पक्षकार को सूचना सहित, अधिनिर्णायक से किन्हीं संगणना गलतियों, किन्हीं लेखन या टंकण-संबंधी गलतियों या पंचाट में हुई वैसी ही प्रकृति की किन्हीं अन्य गलतियों का सुधार करने का अनुरोध कर सकेगा ।

- (2) यदि अधिनिर्णायक उप-विनियम (1) के अधीन किए गए अनुरोध को न्यायानुमत मानता है, तो वह अनुरोध की प्राप्ति से पंद्रह दिनों के भीतर सुधार करेगा जो पंचाट का भाग होगा ।

- (3) अधिनिर्णायक उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट प्रकार की किसी गलती को भी परिशोधित कर सकेगा, स्वप्रेरणा पर, पंचाट की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर ।

साक्ष्य अधिनियम का -
अधिनिर्णायक के समक्ष
कार्यवाहियों में लागू न होना

19. (1)

अधिनिर्णायक के समक्ष कार्यवाहियों में साक्ष्य अधिनियम के अधीन साक्ष्य के कड़े नियम लागू नहीं होंगे और अधिनिर्णायक नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों से संगत उसकी स्वयं की प्रक्रिया अवधारित कर सकेगा ।

(2)

अधिनिर्णायक विनिश्चय करेगा कि क्या साक्ष्य की प्रस्तुति के लिए या मौखिक तर्क के लिए मौखिक सुनवाईयाँ करनी हैं या क्या कार्यवाही दस्तावेजों और अन्य सामग्री आधार पर संचालित की जायेगी ।

परंतु यह कि विनिधानकर्ता के लिए इन विनियमों के अधीन कार्यवाहियों की मौखिक सुनवाई में उपस्थित होना आवश्यक नहीं होगा और अधिनिर्णायक उसके समक्ष प्रस्तुत

किए गए दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर कार्यवाही कर सकेगा ।

- (3) कोई विधि व्यवसायी अधिनिर्णायक के समक्ष कार्यवाहियों में प्रतिवादियों या प्रत्यर्थियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए अनुज्ञात नहीं होगा सिवाय जहां विधि व्यवसायी को अधिनिर्णायक द्वारा शिकायतकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए अनुज्ञात किया गया हो ।

पंचाट की अंतिमता और पुनर्विलोकन की परिस्थितियाँ

20. (1)

इस विनियम के उपबंधों के अधीन, पंचाट अंतिम होगा और क्रमशः पक्षकारों तथा उनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले व्यक्तियों पर बाध्यकारी होगा ।

(2)

न्यायनिर्णयन पर पंचाट द्वारा व्यथित कोई पक्षकार विनियम 17 के अधीन पंचाट या विनियम 18 के अधीन सुधार किए गए पंचाट की प्राप्ति से एक मास के भीतर बोर्ड को पंचाट के पुनर्विलोकन के लिए आधारों को उपवर्णित करते हुए याचिका दाखिल कर

सकेगा ।

- (3) पंचाट का पुनर्विलोकन बोर्ड द्वारा किया जा सकेगा केवल यदि -

(क) पर्याप्त न्यायहानि हुई हो, या

(ख) पंचाट को देखने से ही गलती प्रकट होती हो।

- (4) जहां उप-विनियम (2) के अधीन पंचाट के पुनर्विलोकन के लिए याचिका पक्षकार द्वारा दाखिल की जाती है जिससे पंचाट में उल्लिखित रकम पंचाट के निबंधनों के अनुसार अन्य पक्षकार को अदा की जानी है, ऐसी याचिका बोर्ड द्वारा ग्रहण नहीं की जायेगी जब तक कि याचिका दाखिल करने वाले पक्षकार ने पंचाट में उल्लिखित रकम का पचहत्तर प्रतिशत बोर्ड के पास जमा न कर दिया हो ।

परंतु यह कि बोर्ड, ऐसे कारणों से जो लिखित रूप में अभिलिखित किए जाएंगे, इस उप-विनियम के अधीन जमा की जाने

वाली रकम को अधित्यक्त कर सकेगा या घटा सकेगा ।

(5) बोर्ड पंचाट का पुनर्विलोकन कर सकेगा और ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो यह समुचित समझे ।

(6) बोर्ड पुनर्विलोकन के लिए याचिका के दाखिल किए जाने के पैंतालीस दिनों की कालावधि के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रयास करेगा ।

(7) अधिनिर्णायक द्वारा पारित पंचाट उप-विनियम (2) के अधीन पुनर्विलोकन याचिका दाखिल किए जाने के लिए एक मास की कालावधि के अवसान तक या बोर्ड द्वारा पुनर्विलोकन याचिका का निपटारा किये जाने तक निलंबित रहेगा ।

(8) इस प्रकार निदिष्ट पक्षकार पुनर्विलोकन पर बोर्ड के आदेश की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर या ऐसी कालावधि जो बोर्ड द्वारा पुनर्विलोकन याचिका का निपटारा करने वाले

आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये के भीतर पंचाट का कार्यान्वयन करेगा ।

- (9) बोर्ड पुनर्विलोकन याचिका का निपटारा करने के मामले में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों से संगत इसकी स्वयं की प्रक्रिया अवधारित कर सकेगा और आरंभ में ही याचिका को खारिज कर सकेगा यदि यह उप-विनियम (3) में विनिर्दिष्ट आधारों में से किसी का समाधान नहीं करती है ।

व्यय और ब्याज

21. (1) अधिनिर्णायक या बोर्ड, यथास्थिति, उचित प्रतिकर पंचाट की तुष्टि की तारीख तक ऐसी दर पर ब्याज के साथ जिसमें भावी ब्याज सम्मिलित है अधिनिर्णीत करने का हकदार होगा जो एक प्रतिशत प्रति मास से अधिक नहीं हो सकेगा ।

- (2) पंचाट के मामले में अधिनिर्णायक, या पंचाट के पुनर्विलोकन के लिए याचिका में पारित आदेश के मामले में बोर्ड, यथास्थिति, पंचाट में कार्यवाहियों के व्यय को अवधारित कर सकेगा और इसे पंचाट में या यथास्थिति,

आदेश में सम्मिलित कर सकेगा ।

- (3) अधिनिर्णायक या बोर्ड शिकायत या पुनर्विलोकन के लिए किसी याचिका, जो तुच्छ है को दाखिल करने के लिए शिकायतकर्ता पर व्यय अधिरोपित कर सकेगा।

अध्याय V

पंचाट का कार्यान्वयन

पंचाट के गैर-कार्यान्वयन के परिणाम 22. (1)

पंचाट का कार्यान्वयन अधिनिर्णायक से पंचाट या पुनर्विलोकन याचिका में पारित बोर्ड के आदेश की प्राप्ति के एक मास के भीतर अथवा पंचाट या बोर्ड के आदेश में यथा विनिर्दिष्ट ऐसी कालावधि के भीतर इस प्रकार निदिष्ट पक्षकार द्वारा किया जायेगा ।

(2) यदि कोई व्यक्ति पंचाट या पुनर्विलोकन याचिका में पारित बोर्ड के आदेश का कार्यान्वयन करने में असफल रहता है, उचित कारण के बिना, तो -

(क) वह विनिधानकर्ताओं के शिकायत-मुद्दों को दूर करने में असफल हुआ समझा जायेगा और अधिनियम की धारा 15ग के अधीन शास्ति का दायी होगा ;

(ख) वह -

- (i) अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कार्रवाई ; या
- (ii) प्रतिभूतियों के निलंबन या असूचीबद्धता ; या
- (iii) प्रतिभूति बाजार में पहुंच रखने से विवर्जित किये जाने ; या
- (iv) प्रतिभूतियों में व्यौहार करने से विवर्जित किये जाने ; या
- (v) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के निलंबन या रद्दकरण के लिए कार्रवाई ; या
- (vi) ऐसी अन्य अनुज्ञेय कार्रवाई जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में समुचित समझी जाये

के लिए भी दायी होगा ।

परंतु यह कि कोई ऐसी आदेश सुसंगत नियमों या विनियमों के अधीन अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना पारित नहीं किया जायेगा ।

अध्याय VI

अधिनिर्णायक की विशिष्टियों का प्रदर्शन

कार्यालय परिसर में
अधिनिर्णायक की
विशिष्टियों का प्रदर्शन और
दस्तावेज

23. (1) प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी या मध्यवर्ती बोर्ड द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अधिनिर्णायक का नाम और पता प्रदर्शित करेगा जिसको शिकायतें किर्ली व्यायत पक्षकार द्वारा इसके कार्यालय परिसर में ऐसी रीति में और ऐसे स्थान पर की जानी हैं, ताकि इसे सूचीबद्ध कंपनी या मध्यवर्ती के कार्यालय परिसर में आनेवाले शेयरधारकों या विनिधानकर्ताओं या यूनिट धारकों की सूचना में लाया जा सके ।
- (2) सूचीबद्ध कंपनी या मध्यवर्ती इसके प्रस्ताव दस्तावेज या ग्राहकों के करार में इन विनियमों के अधीन अधिनिर्णायक के माध्यम से शिकायत-मुद्दे निवारण तंत्र के बारे में पूर्ण प्रकटीकरण देंगे ।
- (3) उप-विनियम (2) के अधीन अधिनिर्णायक के माध्यम से शिकायत-मुद्दे निवारण तंत्र को प्रकट करने में हुई कोई असफलता या उप-

विनियम (1) के अनुसार विशिष्टियों को प्रदर्शित करने में हुई कोई असफलता अधिनियम की धारा 15क में अंतर्विष्ट शास्तिक उपबंधों को आकृष्ट करेगी ।

कठिनाइयों का निराकरण 24.

यदि इन विनियमों के उपबंधों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई पैदा होती है, तो बोर्ड ऐसे निदेश या स्पष्टीकरण जारी कर सकेगा जैसा यह कठिनाई का निराकरण करने के लिए आवश्यक या समीचीन समझे ।

अनुसूची

प्ररूप

[भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अधिनिर्णायक) विनियम, 2003 के विनियम 14 के अधीन]

(केवल कार्यालय प्रयोग के लिए)

वर्षकी शिकायत सं.....

तारीख

(शिकायतकर्ता द्वारा भरे जाने के लिए)

प्रति

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड / अधिनिर्णायक

(* बोर्ड के कार्यालय का पता या अधिकारिता रखनेवाले अधिनिर्णायक का पता दें)

प्रिय महोदय,

विषय : (सूचीबद्ध कंपनी / मध्यवर्ती का नाम) के खिलाफ शिकायत

1. शिकायतकर्ता का नाम

2. शिकायतकर्ता का पूरा पता

.....

.....

.....

पिन कोड

दूरभाष सं. / फैक्स सं.

3. जिसके खिलाफ शिकायत है (सूचीबद्ध कंपनी /

मध्यवर्तियों के का नाम और पूरा पता)

पिन

दूरभाष सं. / फैक्स सं.

4. (क) सूचीबद्ध कंपनी / मध्यवर्ती को शिकायतकर्ता द्वारा अभ्यावेदन / शिकायत की तारीख

.....

(कृपया अभ्यावेदन की तीन प्रतियाँ संलग्न करें)

(ख) क्या शिकायतकर्ता द्वारा कोई अनुस्मारक भेजा गया था ? हाँ / नहीं

(यदि हाँ, तो कृपया अनुस्मारकों की तीन प्रतियाँ संलग्न करें)

5. शिकायत की विषय वस्तु / आधार

(कृपया विनियम के विनियम 14 का संदर्भ ले)

.....

6. शिकायत के ब्यौरे (यदि जगह पर्याप्त नहीं है, तो कृपया पृथक् पत्रा संलग्न करें)

.....

7. (क) क्या कोई उत्तर (संबद्ध सूचीबद्ध कंपनी / मध्यवर्ती द्वारा अभ्यावेदन प्राप्त किये जाने के पश्चात् एक मास की कालावधि के भीतर) प्राप्त किया गया है?

हाँ/नहीं

(यदि हाँ, तो कृपया सूचीबद्ध कंपनी / मध्यवर्ती के उत्तर की 'तीन प्रतियाँ' संलग्न करें)

- (ख) क्या अभ्यावेदन अस्वीकार किया गया है?

हाँ/नहीं

(यदि हाँ, तो कृपया अस्वीकृति पत्र की 'तीन प्रतियाँ' संलग्न करें)

- (ग) क्या शिकायतकर्ता ने सूचीबद्ध कंपनी / मध्यवर्ती का कोई अन्य अंतिम विनिश्चय प्राप्त किया है?

हाँ/नहीं

(यदि हाँ, तो कृपया सूचीबद्ध कंपनी / मध्यवर्ती के इसका अंतिम विनिश्चय पहुँचानेवाले पत्र की 'तीन प्रतियाँ' संलग्न करें)

8. अधिनिर्णायक से चाहे गये अनुतोष का स्वरूप

.....

(कृपया अपने दावे के समर्थन में, दस्तावेजी सबूत, यदि कोई हो, की 'तीन प्रतियाँ' संलग्न करें)

9. संलग्न दस्तावेजों की सूची

(कृपया समस्त दस्तावेजों की 'तीन प्रतियाँ' संलग्न करें)

10. घोषणा

1. मैं/हम, शिकायतकर्ता, इसमें घोषणा करता हूँ / करते हैं कि:
 - (क) इसमें ऊपर दी गयी जानकारी सत्य और सही है; और
 - (ख) मैंने / हमने पूर्वोक्त कालमों और एतद्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कथित किसी तथ्य को छिपाया नहीं है / का दुर्व्यपदेशन नहीं किया है।
2. शिकायत विनियम के उपबंधों के अनुसार गिनी गयी एक वर्ष की कालावधि के अवसान से पहले दाखिल की गयी है।
3. (क) वर्तमान शिकायत की विषय वस्तु को मेरी / हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार मेरे द्वारा / या हममें में से किसी एक द्वारा या विषय वस्तु से संबद्ध पक्षकारों में से किसी द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड / अधिनिर्णायक के कार्यालय के समक्ष कभी लाया नहीं गया है।
- (ख) वर्तमान शिकायत की विषय वस्तु उसकी बाबत नहीं है जिसे भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड / अधिनिर्णायक के कार्यालय द्वारा किन्हीं पूर्वर्तन कार्यवाहियों में निपटाया गया था।
- (ग) वर्तमान शिकायत की विषय वस्तु का विनिश्चय किसी अधिकरण / न्यायालय / मध्यस्थ द्वारा नहीं किया गया है।

अथवा

वर्तमान शिकायत की विषय वस्तु (कृपया तारीख का उल्लेख करें जब मामला दाखिल किया गया) से (*कृपया अधिकरण / न्यायालय / मध्यस्थ जिसके समक्ष लंबित है के नाम का उल्लेख करें.....) के समक्ष लंबित है और कार्यवाहियों में इसके अंतिम न्यायनिर्णयन में दीर्घतर समय लगने की संभावना है जैसा विनियम में अनुध्यात है।

4. मैं / हम सूचीबद्ध कंपनी / मध्यवर्ती को हमारे द्वारा दी गयी ऐसी कोई भी जानकारी / दस्तावेजों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड / अधिनिर्णायक को प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ / करते हैं और जिसका प्रकटीकरण भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड / अधिनिर्णायक की राय में किसी अन्य शिकायत या हमारी शिकायत को दूर करने के लिए आवश्यक और अपेक्षित है ।
5. मैंने / हमने भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अधिनिर्णायक) विनियम, 2003 के उपबंधों पर सावधानी से विचार किया है ।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

(शिकायतकर्ता)

नामनिर्देशन / प्राधिकरण - (यदि शिकायतकर्ता अपने प्रतिनिधि, विधि व्यवसायी न होनेवाला, को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड / अधिनिर्णायक के समक्ष या भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड / अधिनिर्णायक के कार्यालय में उपस्थित होने और प्रस्तुतीकरण करने के लिए नामनिर्दिष्ट / प्राधिकृत करता है, तो निम्नलिखित घोषणा भी प्रस्तुत की जानी चाहिए।)

मैं / हम ऊपर लिखित शिकायतकर्ता इसके द्वारा श्री / श्रीमती
 जो विधि व्यवसायी नहीं हैं और जिसका पता

 है को इस शिकायत की सभी कार्यवाहियों में मेरा / हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए नामनिर्दिष्ट करता हूँ / करते हैं और पुष्टि करता हूँ / करते हैं कि उसके द्वारा किया गया

कोई कथन / स्वीकृति या अस्वीकृति मुझ पर / हम पर बाध्यकारी होगा। उसने मेरी उपस्थिति में नीचे हस्ताक्षर किये हैं।

स्वीकृत

(प्रतिनिधि के हस्ताक्षर)

(शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर)

[फा. सं. भाप्रविबो/विधि/15348/2003]

ज्ञानेन्द्रनाथ बाजपेयी, अध्यक्ष

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 21st August, 2003

Securities and Exchange Board of India (OMBUDSMAN) Regulations, 2003

S.O. 953(E).— In exercise of the powers conferred by section 30, read with sub-section (1) of section 11, of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to provide for the establishment of the office of Ombudsman to redress the grievance of the investors in securities and for matters connected therewith or incidental thereto, namely:-

CHAPTER I

PRELIMINARY

SHORT TITLE AND COMMENCEMENT

1.(1) These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Ombudsman) Regulations, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

Definitions

2. (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992);

(b) "award" means a finding in the form of direction or an order of an Ombudsman given in accordance with these regulations;

(c) "authorised representative" means a person duly appointed and authorised by a complainant or any other party to the complaint to act on his behalf and represent him in the proceedings before the Ombudsman;

(d) "Board" means the Securities and Exchange Board of India established under section 3 of the Act;

(e) "Chairman" means Chairman of the Board;

(f) "complaint" means a representation in writing containing a grievance as specified in regulation 13 of these regulations;

(g) "complainant" means any investor who lodges complaint with the Ombudsman and includes an investors association recognised by the Board.

(h) "intermediary" means and includes a person referred to in section 12 of the Act;

- (i) "investor" means a person who invests or buys or sells or deals in securities;
- (j) "listed company" means a company whose securities are listed on a recognised stock exchange and includes a public company which intends to get its securities listed on a recognised stock exchange;
- (k) "member" means a member of the Board and includes the Chairman;
- (l) "Ombudsman" means any person appointed under regulation 3 of these regulations and unless the context otherwise requires, includes Stipendiary Ombudsman;
- (m) "securities" means Securities as defined in clause (h) of section 2 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956);
- (n) "Stipendiary Ombudsman" means a person appointed under regulation 9 for the purpose of acting as ombudsman in respect of a specific matter or matters in a specific territorial jurisdiction and for which he may be paid such expenses, honorarium or sitting fees as may be determined by the Board from time to time.
- (2) Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Act or in the rules or regulations made under the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or in the rules or regulations made under the Act.

CHAPTER II

ESTABLISHMENT OF OFFICE OF OMBUDSMAN

ESTABLISHMENT AND APPOINTMENT

3. (1) With effect from such date as the Board may, by an order fix, there shall be established an office of Ombudsman for the purposes of these regulations.
- (2) The Board may, on recommendation of a Selection Committee, appoint one or more Ombudsmen for such territorial jurisdiction as may be specified from time to time by an order.
- (3) The Selection Committee referred in sub-regulation (2) shall consist of the following members, namely:-
- (i) a retired judge of a High Court, to be nominated by the Chairman;
 - (ii) an expert in the area relating to financial market operations or having special knowledge and experience of law, finance or economics, to be nominated by the Chairman.
 - (iii) a representative of the Board not below the rank of Executive Director who shall be Secretary of the Selection Committee, to be nominated by the Chairman.
- (4) At the request of the Board, the Selection Committee may also prepare a panel of persons out of which a person may be appointed as Stipendiary Ombudsman.
- (5) The panel under sub-regulation (4) shall remain in force for a maximum period of two years and shall be reconstituted from time to time.

Provided that any person in the existing panel shall be eligible to be included in the reconstituted panel.

LOCATION OF OFFICE

4. (1) Office of the Ombudsman shall be located at the Head Office of the Board and if more than one Ombudsman are appointed then the office of any such Ombudsman may be located at any other office of the Board or any other place as may be specified by the Board from time to time.

Provided that the Stipendiary Ombudsman when appointed for any specific complaint or complaints shall be located at such place as may be specified.

- (2) In order to expedite disposal of complaints, the Ombudsman or Stipendiary Ombudsman, as the case may be, may hold sittings at such places within his area of jurisdiction as may be considered necessary and proper by him.
- (3) The Board may provide the premises and other infrastructures including staff or secretarial assistance for the office of Ombudsman or Stipendiary Ombudsman, as the case may be.

QUALIFICATION

5. In order to be appointed as an Ombudsman a person shall be -

- (i) a citizen of India;
- (ii) of high moral integrity ;
- (iii) not below the age of forty five years of age; and
- (iv) either
 - (a) a retired District Judge or qualified to be appointed a District Judge
 - or
 - (b) having at least ten years experience of service in any regulatory body or

- (c) having special knowledge and experience in law, finance, corporate matters, economics, management or administration for a period not less than ten years, or
- (d) an office bearer of investors' association recognised by the Board having experience in dealing with matters relating to investor protection for a period not less than 10 years.

DISQUALIFICATION

6. (1) A person shall not be qualified to hold the office of the Ombudsman if he -
- (i) is an un-discharged insolvent ;
 - (ii) has been convicted of an offence involving moral turpitude;
 - (iii) has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court;
 - (iv) has been charge sheeted for any offence including economic offences ;
- or
- (v) has been a whole-time director in the office of an intermediary or a listed company and a period of at least 3 years has not elapsed.

TENURE

7. (1) A person appointed as an Ombudsman shall hold office for a term not exceeding five years and shall be eligible for reappointment.

Provided that no person shall hold the office of Ombudsman after attaining the age of seventy years.

- (2) The Board, at any time, before the expiry of the period specified under sub-regulation (1) may terminate the services of the Ombudsman by giving him notice of not less than three months in writing or three months salary and allowances in lieu thereof, and the Ombudsman shall also have the

right to relinquish his office, at any time, before the expiry of period specified under sub-regulation (1), by giving to the Board notice of not less than three months in writing.

REMUNERATION

8. The salary, allowances, honorarium or fee payable to, and other terms and conditions of service of, an Ombudsman shall be determined by the Board from time to time.

STIPENDIARY OMBUDSMAN -

9. (1) Notwithstanding the appointment of Ombudsman under sub-regulation (2) of regulation 3, the Board may appoint a person as a Stipendiary Ombudsman out of the panel prepared under sub-regulation (4) of regulation 3, for the purpose of acting as an Ombudsman in respect of a specific matter or matters in a specific territorial jurisdiction, as may be specified in the order of appointment.

(2) A person shall be eligible to be appointed as Stipendiary Ombudsman who:-

(i) has held a judicial post or an executive office under the Central or State Government for atleast ten years or

(ii) is having experience of at least ten years in matters relating to consumer or investor protection or

(iii) has been a legal practitioner in corporate matters for atleast 10 years or

(iv) has served for a minimum period of ten years in any public financial institution within the meaning of section 4A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) or a regulatory body.

- (3) Save as otherwise specified by the Board, the Stipendiary Ombudsman shall exercise all powers and functions as are vested in a Ombudsman under these regulations.
- (4) The Stipendiary Ombudsman shall be paid such fees or honorarium and allowances for the services rendered by him, as may be determined by the Board from time to time.

TERRITORIAL JURISDICTION –

10. Every Ombudsman or Stipendiary Ombudsman shall exercise jurisdiction in relation to an area as may be specified by the Board by an order.

CHAPTER III

POWERS AND FUNCTIONS OF OMBUDSMAN

GENERAL

11. The Ombudsman shall have the following powers and functions :-
- (a) to receive complaints specified in regulation 13 against any intermediary or a listed company or both;
 - (b) to consider such complaints and facilitate resolution thereof by amicable settlement;
 - (c) to approve a friendly or amicable settlement of the dispute between the parties;
 - (d) to adjudicate such complaints in the event of failure of settlement thereof by friendly or amicable settlement.

OTHER POWERS AND FUNCTIONS

12. (1) The Ombudsman shall -

- (a) draw up an annual budget for his office in consultation with the Board and shall incur expenditure within and in accordance with the provisions of the approved budget;
- (b) submit an annual report to the Board within three months of the close of each financial year containing general review of activities of his office; and
- (c) furnish from time to time such information to the Board as may be required by the Board.

(2) Every financial year of the Ombudsman shall end on 31st March of each year and the annual report shall be given in such form and manner as may be specified by the Board.

CHAPTER IV

PROCEDURE FOR REDRESSAL OF GRIEVANCE

GROUND OF COMPLAINT

13. A person may lodge a complaint on any one or more of the following grounds either to the Board or to the Ombudsman concerned :-

- (i) Non-receipt of refund orders, allotment letters in respect of a public issue of securities of companies or units of mutual funds or collective investments schemes;
- (ii) Non-receipt of share certificates, unit certificates, Debenture certificates, bonus shares;
- (iii) Non-receipt of dividend by shareholders or unit-holders;

- (iv) Non-receipt of interest on debentures, redemption amount of debentures or interest on delayed payment of interest on debentures ;
- (v) Non-receipt of interest on delayed refund of application monies;
- (vi) Non-receipt of annual reports or statements pertaining to the portfolios;
- (vii) Non-receipt of redemption amount from a mutual fund or returns from collective investment scheme;
- (viii) Non-transfer of securities by an issuer company, mutual fund, Collective Investment Management Company or depository within the stipulated time;
- (ix) Non-receipt of letter of offer or consideration in takeover or buy-back offer or delisting;
- (x) Non-receipt of statement of holding corporate benefits or any grievances in respect of corporate benefits, etc;
- (xi) Any grievance in respect of public, rights or bonus issue of a listed company ;
- (xii) Any of the matters covered under section 55A of the Companies Act, 1956;
- (xiii) Any grievance in respect of issue or dealing in securities against an intermediary or a listed company.

PROCEDURE OF FILING COMPLAINT –

- 14(1) Any person who has a grievance against a listed company or an intermediary relating to any of the matters specified in regulation 13 may himself or through his authorised representative or any investors association recognised by the Board, make a complaint against a listed company or an intermediary to the Ombudsman within whose jurisdiction the registered or corporate office of such listed company or intermediary is located.

Provided that if the Board has not notified any Ombudsman for a particular locality or territorial jurisdiction, the complainant may request the Ombudsman located at the Head Office of the Board for forwarding his complaint to the Ombudsman of competent jurisdiction.

(2) The complaint shall be in writing duly signed by the complainant or his authorised representative (not being a legal practitioner) in the Form specified in the Schedule to these regulations and supported by documents, if any.

(3) No complaint to the Ombudsman shall lie -

(a) unless the complainant had, before making a complaint to the Board or the Ombudsman concerned, made a written representation to the listed company or the intermediary named in the complaint and the listed company or the intermediary, as the case may be, had rejected the complaint or the complainant had not received any reply within a period of one month after the listed company or intermediary concerned received his representation or the complainant is not satisfied with the reply given to him by the listed company or an intermediary;

(b) unless the complaint is made within six months from the date of the receipt of communication of rejection of his complaint by the complainant or within seven months after the receipt of complaint by the listed company or intermediary under clause (a) above.

(c) if the complaint is in respect of the same subject matter which was settled through the Office of the Board or Ombudsman concerned in any previous proceedings, whether or not received from the same complainant or along with any one or more or other complainants or any one or more of the parties concerned with the subject matter;

(d) if the complaint pertains to the same subject matter for which any proceedings before the Board or any court, tribunal or arbitrator or any other forum is pending or a decree or award or a final order has already been passed by any such competent authority, court, tribunal, arbitrator or forum.

(e) if the complaint is in respect of or pertaining to a matter for which action has been taken by the Board under Section 11(4) of the Act or Chapter VI A of the Act or under sub-section (3) of section 12 of the Act or under any other regulations made under the Act.

(4) The Ombudsman may dismiss in limine a complaint on any of the grounds specified under sub-regulation (3) or when such complaint is frivolous in his opinion.

POWER TO CALL FOR INFORMATION

15(1) For the purpose of carrying out his duties under these regulations, an Ombudsman may require the listed company or the intermediary named in the complaint or any other person, institution or authority to provide any information or furnish certified copy of any document relating to the subject matter of the complaint which is or is alleged to be in its or his possession:

Provided that in the event of the failure of a listed company or the intermediary to comply with the requisition made under sub-regulation (1) without any sufficient cause, the Ombudsman may, if he deems fit, draw the inference that the information, if provided or copies if furnished, would be unfavourable to the listed company or intermediary.

(2) The Ombudsman shall maintain confidentiality of any information or document coming to his knowledge or possession in the course of discharging his duties and shall not disclose such information or document to any person

except and as otherwise required by law or with the consent of the person furnishing such information or document:

Provided that nothing in sub-regulation (2) shall prevent the Ombudsman from disclosing information or document furnished by a party in a complaint to the other party or parties, to the extent considered by him to be reasonably required to comply with the principles of natural justice and fair play in the proceedings.

Provided further that provisions of sub-regulation (2) shall not apply in relation to the disclosures made or information furnished by the Ombudsman to the Board or to the publication of Ombudsman's award in any journal or newspaper or filing thereof before any Court, Forum or authority.

SETTLEMENT BY MUTUAL AGREEMENT

16(1) As soon as it may be practicable so to do, the Ombudsman shall cause a notice of the receipt of any complaint along with a copy of the complaint sent to the registered or corporate office of the listed company or office of the intermediary named in the complaint and endeavour to promote a settlement of the complaint by agreement or mediation between the complainant and the listed company or intermediary named in the complaint.

(2) If any amicable settlement or friendly agreement is arrived at between the parties, the Ombudsman shall pass an award in terms of such settlement or agreement within one month from the date thereof and direct the parties to perform their obligations in accordance with the terms recorded in the award.

(3) For the purpose of promoting a settlement of the complaint, the Ombudsman may follow such procedure and take such actions as he may consider appropriate.

AWARD ON ADJUDICATION

17 (1) In the event the matter is not resolved by mutually acceptable agreement within a period of one month of the receipt of the complaint or such extended period as may be permitted by the Ombudsman, he shall, based upon the material placed before him and after giving opportunity of being heard to the parties, give his award in writing or pass any other directions or orders as he may consider appropriate.

(2) The award on adjudication shall be made by Ombudsman within a period of three months from the date of the filing of the complaint.

Provided that no award shall be invalidated by reason alone of the fact that the award was made beyond the said period of three months.

(3) The Ombudsman shall send his award to the parties to the adjudication to perform their obligations under the award.

CORRECTION OF AWARD

18 (1) Within fifteen days from the receipt of the award a party, with notice to the other party, may request the Ombudsman to correct any computation errors, any clerical or typographical errors or any other errors of a similar nature occurring in the award.

(2) If the Ombudsman considers the request made under sub-regulation (1) to be justified, he shall make the correction within fifteen days from the receipt of the request which shall form part of the award.

(3) The Ombudsman may also rectify any error of the type referred to in sub-regulation (1), on his own initiative, within fifteen days from the date of the award.

EVIDENCE ACT NOT TO APPLY IN THE PROCEEDINGS BEFORE OMBUDSMAN

19(1) In proceedings before the Ombudsman strict rules of evidence under the Evidence Act shall not apply and the Ombudsman may determine his own procedure consistent with the principles of natural justice.

(2) Ombudsman shall decide whether to hold oral hearings for the presentation of evidence or for oral argument or whether the proceeding shall be conducted on the basis of documents and other materials.

Provided that it shall not be necessary for an investor to be present at the oral hearing of proceedings under these regulations and the Ombudsman may proceed on the basis of the documentary evidence submitted before him.

(3) No legal practitioner shall be permitted to represent the defendants or respondents at the proceedings before the Ombudsman except where a legal

practitioner has been permitted to represent the complainants by the Ombudsman.

FINALITY OF AWARD AND CIRCUMSTANCES OF REVIEW

20.(1) Subject to the provisions of this regulation, an award shall be final and binding on the parties and persons claiming under them respectively.

(2) Any party aggrieved by the award on adjudication may within one month from the receipt of the award under Regulation 17 or corrected award under Regulation 18 may file a petition before the Board setting out the grounds for review of the award.

(3) An award may be reviewed by the Board only if –

(a) there is substantial mis-carriage of justice, or

(b) there is an error apparent on the face of the award.

(4) Where a petition for review of the award under sub-regulation (2) is filed by a party from whom the amount mentioned in the award is to be paid to the other party in terms of the award, such petition shall not be entertained by the Board unless the party filing the petition has deposited with the Board seventy-five percent of the amount mentioned in the award.

Provided that the Board may, for reasons to be recorded in writing, waive or reduce the amount to be deposited under this sub-regulation.

(5) The Board may review the award and pass such order as it may deem appropriate.

(6) The Board shall endeavour to dispose of the matter within a period of forty five days of the filing of the petition for review.

(7) The award passed by the Ombudsman shall remain suspended till the expiry of period of one month for filing review petition under sub-regulation (2) or till the review petition is disposed off by the Board.

(8) The party so directed shall implement the award within 30 days of receipt of the order of the Board on review or within such period as may be specified by the Board in the order disposing off the review petition.

(9) The Board may determine its own procedure consistent with principles of natural justice in the matter of disposing of review petition and may dismiss the petition in limine if it does not satisfy any of the grounds specified in sub-regulation (3).

COST AND INTEREST

21.(1)The Ombudsman or the Board, as the case may be, shall be entitled to award reasonable compensation along with interest including future interest till date of satisfaction of the award at a rate which may not exceed one percent per mensem.

(2) The Ombudsman in the case of an award, or the Board in the case of order passed in petition for review of the award, as the case may be, may determine the cost of the proceedings in the award and include the same in the award or as the case may be, in the order.

(3) The Ombudsman or the Board may impose cost on the complainant for filing complaint or any petition for review, which is frivolous.

CHAPTER V**IMPLEMENTATION OF THE AWARD****CONSEQUENCES OF NON-IMPLEMENTATION OF THE AWARD**

22. (1) The award shall be implemented by the party so directed within one month of receipt of the award from the Ombudsman or an order of the Board passed in review petition or within such period as specified in the award or order of the Board.

(2) If any person fails to implement the award or order of the Board passed in the review petition, without reasonable cause -

- (a) he shall be deemed to have failed to redress investors' grievances and shall be liable to a penalty under section 15C of the Act;
- (b) he shall also be liable for -
 - (i) an action under section 11 (4) of the Act ; or
 - (ii) suspension or delisting of securities; or
 - (iii) being debarred from accessing the securities market; or
 - (iv) being debarred from dealing in securities; or
 - (v) an action for suspension or cancellation of certificate of registration; or
 - (vi) such other action permissible which may be deemed appropriate in the facts and circumstances of the case.

Provided that no such order shall be passed without following the procedure laid down under the relevant rules or regulations.

CHAPTER VI

DISPLAY OF THE PARTICULARS OF THE OMBUDSMAN

DISPLAY OF THE PARTICULARS OF THE OMBUDSMAN IN OFFICE PREMISES AND DOCUMENTS

23(1) Every listed company or intermediary shall display the name and address of the Ombudsman as specified by the Board to whom the complaints are to be

made by any aggrieved person in its office premises in such manner and at such place, so that it is put to notice of the shareholders or investors or unit holders visiting the office premises of the listed company or intermediary.

(2) The listed company or intermediary in its offer document or clients agreement shall give full disclosure about the grievance redressal mechanism through Ombudsman under these regulations.

(3) Any failure to disclose the grievance redressal mechanism through Ombudsman under sub-regulation (2) or any failure to display the particulars as per sub-regulation (1) shall attract the penal provisions contained in Section 15A of the Act.

REMOVAL OF DIFFICULTIES

24. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of these regulations, the Board may issue such directions or clarifications as it may think necessary or expedient for removing the difficulty.

SCHEDULE

FORM

[Under regulation 14 of the Securities and Exchange Board of India
(Ombudsman) Regulations, 2003]

(FOR OFFICE USE ONLY)

Complaint No.of year

Date

(TO BE FILLED UP BY THE COMPLAINANT)

To

The Securities and Exchange Board of India/ Ombudsman

(* give address of the office of the Board or the address of the Ombudsman
having jurisdiction

Dear Sir,

Sub: Complaint against(Name of the listed company /
intermediary)

1. NAME OF THE COMPLAINANT

2. FULL ADDRESS OF THE COMPLAINANT
.....
.....

PIN CODE

PHONE NO. / FAX NO.

**3. COMPLAINT AGAINST (NAME AND FULL
ADDRESS OF THE LISTED COMPANY /
INTERMEDIARIES)**

PIN

PHONE NO. / FAX NO.

**4. (a) DATE OF REPRESENTATION / COMPLAINT BY THE COMPLAINANT
TO
THE LISTED COMPANY / INTERMDIARY**

(Please enclose three copies of the representation)

(b) Whether any reminder was sent by the complainant? YES / NO
(If yes, please enclose three copies of the reminder)

5. SUBJECT MATTER/GROUNDS OF THE COMPLAINT
(Please refer to regulation 14 of the Regulations)

6. DETAILS OF THE COMPLAINT (If space is not sufficient, please enclose
separate sheet)

7. (a) Whether any reply (Within a period of one month after the listed company /
intermediary concerned received the representation) has been received?
YES / NO
(If yes, please enclose 'three copies' of the reply of the listed company /
intermediary)

(b) Whether the representation has been rejected ? YES/ NO
(If yes, please enclose 'three copies' of the letter of rejection)

(c) Whether the complainant has received any other final decision of the listed
company / intermediary?
YES/ NO
(If yes, please enclose 'three copies' of the letter of the listed
company/intermediary conveying its final decision)

8. NATURE OF RELIEF SOUGHT FROM THE OMBUDSMAN

(Please enclose '**three copies**' of documentary proof, if any, in support of your claim)

9. LIST OF DOCUMENTS ENCLOSED

(Please enclose '**three copies**' of all the documents)

10. DECLARATION

1. I/ We , the complainant/s herein declare that:

(a) the information furnished herein above is true and correct; and

(b) I/ We have not concealed or misrepresented any fact stated in aforesaid columns and the documents submitted herewith.

2. The complaint is filed before expiry of period of one year reckoned in accordance with the provisions of the Regulations.

3. (a) The subject matter of the present complaint has never been brought before the Office of the Securities and Exchange Board of India /Ombudsman by me/ or by any one of us or by any of the parties concerned with the subject matter to the best of my/ our knowledge.

(b) The subject matter of the present complaint is not in respect of the same which was settled through the Office of the Securities and Exchange Board of India /Ombudsman in any previous proceedings

(c) The subject matter of the present complaint has not been decided by any forum/court/arbitrator.

OR

The subject matter of the present complaint is pending since..... (**please mention the date when the matter was filed**) before (***Please mention the name of the forum/court/arbitrator before whom pending**) and the proceedings are likely to take longer time in its final adjudication as contemplated in the Regulations.

4. I/We authorise the listed company / intermediary to disclose any such information/ documents furnished by us to the Securities and Exchange Board of India /Ombudsman and disclosure whereof in the opinion of the Securities and Exchange Board of India/ Ombudsman is necessary and is required for redressal of any other complaint or our complaint.

5. I/We have carefully gone through the provisions of the Securities and Exchange Board of India (Ombudsman) Regulations, 2003.

Yours faithfully

(Signature)

(Complainant)

NOMINATION / AUTHORISATION - (If the complainant wants to nominate/authorise his representative, not being a legal practitioner, to appear and make submissions on his behalf before the Securities and Exchange Board of India/ Ombudsman or to the Office of the Securities and Exchange Board of India/ Ombudsman, the following declaration should also be submitted.)

I/We the above named complainant/s hereby nominate Shri/Smt..... who is not a legal practitioner and whose address is

.....
as my/our REPRESENTATIVE in all proceedings of this complaint and confirm that any statement, acceptance or rejection made by him/her shall be binding on me/us. He/She has signed below in my presence.

ACCEPTED

(Signature of Representative)

(Signature of Complainant)

[F.No. SEBI/LGL/15348/2003]

G. N. BAJPAI, Chairman